RNI : UAHIN/25/A3210

आवाम इंडिया

हिन्दी साप्ताहिक

वर्षः 01 अंकः 06 देहरादून, शुक्रवार 15 मई 2026 मूल्य 2 रुपये पृष्ठः 8 www.aawamindia.com

कैबिनेट बैठकः सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे घोषित किया जाएगा

देहरादून। कैबिनेट बैठक में वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के दृष्टगित प्रधानमंत्री के आवाहन पर प्रदेश में अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक सुधार लागू करने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्तमान हालात में नागरिकों से छोटे-छोटे व्यवहारिक बदलावों के माध्यम से राष्ट्रीय प्रयासों में सहयोग की अपील की है। जिसका जनसामान्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

वर्क फ्रॉम होम

सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को बढावा दिया जाएगा। निजी क्षेत्रों में भी वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही लोगों को सार्वजनिक परिवहन के अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

नो व्हीकल डे

मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगणों के वाहन फ्लीट में वाहनों की संख्या आधी की जाएगी। सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे घोषित किया जाएगा।

वर्क फ्रॉम होम के तहत घर से ही कार्य करेंगे। जन सामान्य को भी सप्ताह में एक दिन ष्छव टमीपबसम क्लष के लिए प्रेरित किया जाएगा।

सरकारी एवं निजी भवनों में ।ब के प्रयोग को सीमित करने के प्रयास किए जाएंगे।

एक अधिकारी, एक वाहन

परिवहन विभाग को सार्वजनिक बसों की सेवा और क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन के उपयोग हेतु प्रेरित किया जाएगा। जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक विभाग हैं, उनके द्वारा एक दिन

में अधिकतम एक वाहन का इस्तेमाल किया जाएगा।

ईवी पॉलिसी

इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए जल्द ही प्रभावी ईवी पॉलिसी लाई जाएगी, नए सरकारी वाहनों के क्रय में 50 प्रतिशत अनिवार्य तौर पर EV होंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए चार्जिंग स्टेशन / नेटवर्क का प्राथमिकता के आधार पर विस्तार किया जाएगा।

सरकारी विदेश यात्राएं सीमित होंगी

सरकारी विदेशी यात्राओं को सीमित किया जाएगा।

"Visit My State अभियान के माध्यम से घरेलू पर्यटन को बढावा दिया जाएगा। राज्य में विरासत, धार्मिक, वेलनेस, ग्रामीण और इको-टूरिज्म सर्किटों के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

राज्य में Destination Weddings को प्रोत्साहन और Single Window Clearance की व्यवस्था की जाएगी। उत्तराखंड इस दिशा में पहले ही पहल कर चुका है। प्रवासी भारतीयों को उत्तराखंड में छुट्टियां बिताने हेतु प्रेरित किया जाएगा।

'मेरा भारत, मेरा योगदान'

'मेरा भारत, मेरा योगदान' जैसे जन-जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। "Made in State" अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों की बिक्री बढ़ाई जाएगी। सरकारी खरीद में "Make in India" नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

नागरिकों को एक वर्ष तक सोने की खरीद को सीमित करने के लिए जागरुक किया जाएगा।

खाद्य तेल की खपत घटाना

आम जनमानस को कम तेल वाले भोजन से होने वाले स्वास्थ्य लाभों पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी कैंटीनों में तेल उपयोग की समीक्षा करते हुए उसके उपयोग में कमी लाए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

होटल, ढाबा और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को स्वू-व्पस डमदनष अपनाने हेतु प्रेरित किया जाएगा।

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा

किसानों को Natural Farming, Zero Budget Farming और Bio-inputs का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उर्वरकों के संतुलित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा

PNG (Piped Natural Gas) कनेक्शनों के संयोजनों को मिशन मोड में चलाया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और सरकारी आवासों में PNG उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी।

PM Surya Ghar Yojana के अंतर्गत Rooftop Solar को बढ़ावा दिया जाएगा। गोबर गैस को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज विभाग और ग्राम्य विकास विभाग को निर्देशित किया गया।

Mining, Solar और Power Projects की मंजूरी प्रदान करने में तेजी लायी जाएगी। मुख्यसचिव की अध्यक्षता में गठित एचपीसी 60 दिन में प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करेगी।

प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य कर रहीः सुबोध उनियाल

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं उत्तराखण्ड के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा देहरादून में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कुल 307 चिकित्साधिकारियों, फार्मासिस्टों तथा उद्यान विभाग के अंतर्गत नव नियुक्त प्रयोगशाला सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने एवं युवाओं को पारदर्शी तरीके से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

एक समय भर्ती प्रक्रियाएं नकल एवं भ्रष्टाचार के कारण प्रभावित होती थीं, जिससे योग्य युवाओं का विश्वास व्यवस्था से कमजोर पड़ने लगा था। प्रदेश सरकार ने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाया है, ताकि प्रत्येक परीक्षा एवं नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने कहा कि बीते चार वर्षों में प्रदेश सरकार द्वारा 32,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर प्रदान किए गए हैं। यह केवल रोजगार नहीं, बल्कि युवाओं के विश्वास, न्याय एवं सुशासन की स्थापना का प्रमाण है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, खजान दास, विधायक उमेश शर्मा काऊ, सविता हरबंस कपूर तथा देहरादून नगर निगम के महापौर सौरभ थपलियाल उपस्थित रहे।

गोल्डन फारेस्ट के खातों में डीएम ने पकड़ी अवैध गैरकानूनी 150 रजिस्ट्री

संवाददाता

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल द्वारा उप निबंधक कार्यालय विकासनगर में किए गए औचक निरीक्षण स्टाम्प चोरी व गंभीर अनियमितताओं का बड़ा खुलासा हुआ है। निरीक्षण के दौरान उप रजिस्ट्रार कार्यालय विकासनगर में चल रहे स्टांप चोरी एवं अवैधानिक रजिस्ट्रियों के मामले सामने आए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने उप निबंधक विकासनगर अपूर्वा सिंह के निलंबन एवं विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति शासन को भेज दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई को राजस्व हितों की सुरक्षा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण तथा पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा विगत 4 मई को उप निबंधक कार्यालय विकासनगर में औचक निरीक्षण/छापेमारी की गई थी।

निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर कार्यालय से महत्वपूर्ण अभिलेख जब्त किए गए थे।

मूल विलेख पत्र वर्षों तक कार्यालय में रोके गए :- निरीक्षण के दौरान वर्ष 2018, 2024 एवं 2025 तक के मूल विलेख पत्र कार्यालय में संदिग्ध स्थिति में पाए गए। कई पंजीकृत दस्तावेज महीनों एवं वर्षों तक कार्यालय में रोके जाने के तथ्य भी सामने आए हैं। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित अभिलेख तत्काल जब्त कर जांच प्रारंभ कर दी है। कार्यालय में 25 रजिस्ट्रीयां वर्षों से बगैर किसी कारण अभिलिखित तथा सूचना के डम्प पाई गई थी,जिसका कारण जानने पर संतोषजन उत्तर नही मिला।

गोल्डन फॉरेस्ट की प्रतिबंधित भूमि की रजिस्ट्रियां उजागर, तत्कालीन कार्मिकों की भूमिका की भी जांच:- निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश द्वारा बाधित गोल्डन फारेस्ट के खातों में 150 अवैध गैरकानूनी रजिस्ट्री पकड़ी है। प्रारंभिक जांच में विक्रय हेतु प्रतिबंधित भूमि की रजिस्ट्रियां किए जाने के मामले भी सामने आए हैं, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। जांच के दौरान गोल्डन फॉरेस्ट की प्रतिबंधित भूमि की सैकड़ों रजिस्ट्रियां किए जाने की जानकारी भी प्राप्त हुई है, जिसमें तत्कालीन कार्यरत कर्मचारियों की भूमिका भी की भी जांच की जा रही है।

जिला प्रशासन के अनुसार इस प्रकार की अवैधानिक रजिस्ट्रियों से न केवल राजस्व की क्षति हुई बल्कि भूमि क्रेताओं के साथ धोखाधड़ी जैसी स्थिति भी उत्पन्न हुई है। निरीक्षण एवं प्रारंभिक जांच में धारा 47-ए के अंतर्गत स्टांप शुल्क चोरी से संबंधित 47 प्रकरण चिन्हित किए गए हैं।

जिला प्रशासन के अनुसार यह करोड़ों रुपये के राजस्व नुकसान से जुड़ा गंभीर मामला हो सकता है। मामलों में नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी तथा संबंधित अधिकारियों एवं कार्मिकों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। निरीक्षण के दौरान कार्यालय संचालन में पारदर्शिता की कमी, अभिलेखों के रखरखाव में लापरवाही, प्रक्रियात्मक नियमों के उल्लंघन तथा रिकॉर्ड प्रबंधन में गंभीर खामियां भी सामने आई हैं। जिलाधिकारी ने इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत जांच कर समग्र रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

जिला प्रशासन द्वारा वर्तमान के साथ-साथ पूर्व में तैनात सभी सब-रजिस्ट्रारों के कार्यकाल के दौरान हुई संदिग्ध गतिविधियों की भी गहन जांच की जा रही है। प्रकरण से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शासन को प्रेषित की जा रही है, ताकि दोषियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय एवं विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री के निर्देशन में जिला प्रशासन देहरादून द्वारा राजस्व एवं भूमि संबंधी मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, भ्रष्टाचार अथवा अनियमितता के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है।

जिला प्रशासन की सरकार एवं शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शी, जवाबदेह एवं जनहितकारी प्रशासन सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा भविष्य में भी इस प्रकार लगातार एक्शन देखने को मिल सकते हैं।

मोतीलाल नेहरू मार्ग की खराब स्थिति पर मंत्री ने जताई नाराजगी

संवाददाता

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज अपने कैंप कार्यालय में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मोटर मार्ग निर्माण से संबंधित विभिन्न प्रस्तावित एवं संचालित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ विभिन्न सड़क परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने क्यारा-धनौल्टी मार्ग, गढ़-बुरांसखण्डा मार्ग, मोटीधार-मसराना, लोहारीगढ़, कोठियाना, छोटी छमरौली से डोमकोट, विलासपुर कांडली, अनारवाला-मालसी सहित देहरादून के विभिन्न वार्डो की सड़क की स्थिति एवं प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने गजियावाला, अमन विहार एवं धोरण पुल की स्थिति की जानकारी भी ली। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी लंबित सड़क निर्माण एवं सुधारीकरण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किया जाए।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के मोतीलाल नेहरू मार्ग की खराब स्थिति पर नाराजगी जताते हुए तत्काल मरम्मत कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वह स्वयं 16 मई को मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करेंगे, इसलिए उससे पूर्व मार्ग की मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया जाए। मंत्री ने मसूरी मॉल रोड के सुधारीकरण कार्यों को भी प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश देते हुए जोहड़ी अनारवाला क्षेत्र में चल रहे सड़क सुधारीकरण कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए गए।

बैठक में गढ़ी डाकरा क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण कार्यों को लेकर भी चर्चा की गई।

इस अवसर पर लोनिवि के प्रमुख अभियंता राजेश शर्मा, अधीक्षण अभियंता ओपी सिंह, ईई राजेश कुमार, मण्डल अध्यक्ष राजीव गुरुंग, समीर पुण्डीर, अनुज कौशल, विष्णु गुप्ता, संजय नौटियाल आदि उपस्थित रहे।

ऊर्जा संसाधनों का सीमित इस्तेमाल करने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने की फ्लीट में कटौती

देहरादून। पश्चिम एशिया में चल रहे विवाद के बीच भारत सरकार लगातार इस बात जोर दे रही है

कि ऊर्जा संसाधनों का सीमित इस्तेमाल किया जाए। इसी बीच पीएम की ओर से हैदराबाद रैली में लोगों को संबोधित करते हुए पेट्रोल, एलपीजी गैस की खपत कम करने और अगले एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की थी।

पीएम ने कहा कि पश्चिम एशिया में संकट के बीच विदेशी मुद्रा संरक्षण के लिए पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने, शहरों में मेट्रो रेल सेवाओं का उपयोग करने, कारपूलिंग करने, इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिक उपयोग करने, पार्सल परिवहन के लिए रेलवे सेवाओं का उपयोग करने और घर से काम करने का सुझाव दिया।

प्रधानमंत्री की ओर से की गई अपील का असर अब देश भर में दिखाई देने लगा है. उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और भाजपा विधायक प्रेमचंद अग्रवाल स्कूटी से आवाजाही करते दिखाई दिए। तो वहीं अब दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की फ्लीट में भी कटौती कर दी गई है।

प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक की घटनाएं युवाओं के हितों पर कुठाराघात: गणेश गोदियाल

संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को पत्र लिखकर प्रतियोगी परीक्षाओं के बार-बार हो रहे पेपर लीक मामलों को युवा हितों पर कुठाराघात बताते हुए कहा है कि पिछले कुछ वर्षों से देश में जिस प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं विषेशकर नीट और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जैसी परीक्षाओं मे पेपर परीक्षा से पूर्व पेपर लीक हो रहे हैं उससे परीक्षा का आयोजन करने वाली ऐजेंसियों और सरकार की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा प्रश्नचिन्ह खड़ा हो गया है तथा पेपर लीक की घटनाओं में सत्ताधारी दल के लोगों की संलिप्तता ने सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता को ही संदिग्ध बना दिया है।

प्रदेश कांग्रेस मीडिया कमेटी के चेयरमैन राजीव महर्षि ने विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को लिखे पत्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि देश की सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रवेश परीक्षा नीट में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक, अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के मामलों ने लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का विश्वास गंभीर रूप से प्रभावित किया है। चिकित्सा प्रवेश परीक्षा नीट में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और धांधली के मामलों ने लाखों मेहनती छात्रों और उनके अभिभावकों का विश्वास तोडने का काम किया है। यह केवल एक परीक्षा में गड़बडी का मामला नहीं, बल्कि

देश की शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। वर्षों की कठिन मेहनत आर्थिक संसाधनों और मानसिक दबाव के बीच परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के भविष्य के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण एवं चिंताजनक है।

गणेश गोदियाल ने कहा कि आज देश का युवा दिन-रात मेहनत करके अपने भविष्य का सपना देखता है, लेकिन जब परीक्षाओं की गोपनीयता ही सुरक्षित न रहे तो प्रतिभाशाली और ईमानदार छात्रों का मनोबल टूटना स्वाभाविक है। केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए पारदर्शी और मजबूत परीक्षा प्रणाली लागू करें। गत वर्षो में नीट और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा सहित अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े पेपर लीक, सॉल्वर गैंग, फर्जी परीक्षार्थियों तथा परीक्षा केंद्रों में अनियमितताओं के अनेक मामले सामने आए हैं जिनमें सत्ताधारी दल के लोगों की संलिप्तता गम्भीर चिन्ता का विषय है। इन घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि परीक्षा प्रणाली में गंभीर खामियां मौजूद हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि हर वर्ष जांच और सख्ती के दावे किए जाते हैं, लेकिन फिर भी परीक्षा की विश्वसनीयता पर लगातार प्रश्नचिन्ह लग रहे हैं।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना सरकार और परीक्षा एजेंसियों की नैतिक एवं संवैधानिक जिम्मेदारी है। यदि प्रतिभाशाली और मेहनती विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिलेगा तो युवाओं का व्यवस्था से विश्वास उठना स्वाभाविक है। नीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में जिन लोगों ने पैसे और प्रभाव के दम पर मेहनती विद्यार्थियों के अधिकारों को कुचलने का प्रयास किया है, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए।

कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री से मांग करते हुए कहा कि:-

नीट परीक्षा में हुए सभी पेपर लीक एवं अनियमितताओं की माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज की निगरानी में उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष न्यायिक जांच कराई जाए।

परीक्षा संचालन में शामिल दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं संगठित गिरोहों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए।

परीक्षा केंद्रों पर आधुनिक तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था लागू की जाए, जिसमें लाइव सीसीटीवी मॉनिटरिंग एवं बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य हो।

परीक्षा प्रणाली को पूर्णत: पारदर्शी एवं सुरक्षित बनाने हेतु स्वतंत्र निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए।

प्रभावित अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा हेतु आवश्यक होने पर पुन: परीक्षा आयोजित की जाए।

भविष्य में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पेपर लीक रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सख्त कानून बनाया जाए।

गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सभी छात्रों के साथ खडी है और केन्द्र सरकार से आशा करती है कि भविष्य में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को पूर्ण पारदर्शिता, सुरक्षा और निष्पक्षता के साथ आयोजित किया जाए, ताकि युवाओं का विश्वास लोकतांत्रिक व्यवस्था और शिक्षा प्रणाली पर बना रहे।

पुलिस ने स्कूली बच्चों को पढ़ाया साइबर, महिला व सड़क सुरक्षा का पाठ

संवाददाता

उत्तरकाशी। महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु संचालित "अभया" अभियान के अंतर्गत उत्तरकाशी पुलिस

टीम द्वारा ऐंजेल इंटरनेशनल एकेडमी एवं अजीम प्रेमजी स्कूल, मातली में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को साइबर अपराध, महिला सुरक्षा, बाल संरक्षण, मानव तस्करी, नशे के दुष्प्रभाव एवं सड़क सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक किया गया।

कार्यक्रम के दौरान उपनिरीक्षक श्रीमती गीता, प्रभारी महिला काउंसलिंग सेल ने छात्राओं को महिला एवं बाल सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए गुड टच-बैड टच, अच्छे-बुरे व्यवहार की पहचान, नशे के दुष्प्रभाव तथा साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए। बच्चों को पोक्सो एक्ट व बाल विवाह की जानकारी देते हुये उन्होंने उत्तराखण्ड पुलिस ऐप, गौरा शक्ति फीचर, डायल-112 एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की उपयोगिता बताते हुये छात्राओं को आपात स्थिति में इनके प्रभावी उपयोग के लिए प्रेरित किया। वहीं आरक्षी नवीन रमोला ने बच्चों को मानव तस्करी एवं बाल अपराधों के प्रति सजग करते हुए अनजान एवं संदिग्ध व्यक्तियों से सतर्क रहने, किसी के बहकावे में न आने तथा मोबाइल फोन एवं सोशल मीडिया के दुरुपयोग से होने वाले खतरों के प्रति सचेत किया।

चारधाम यात्रा के मद्देनजर पुलिस टीम द्वारा छात्र-छात्राओं को वर्तमान में संचालित चारधाम यात्रा की संक्षिप्त जानकारी देते हुए यात्रा के दौरान पुलिस द्वारा किए जा रहे यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण एवं अन्य व्यवस्थाओं का व्यावहारिक अनुभव साझा किया गया। यात्रा के दौरान बढ़ते यातायात दबाव के बीच बच्चों को सड़क पर सावधानी बरतने और यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गयाइस अवसर पर वेद्प्रकाश सेमवाल (प्रधानाचार्य, ऐंजेल इंटरनेशनल एकेडमी), सुनील बिष्ट (प्रधानाचार्य, अजीम प्रेमजी स्कूल), अपर उपनिरीक्षक श्रीमती माया असवाल, कांस्टेबल वीरेन्द्र नेगी सहित विद्यालय के शिक्षकगण उपस्थित रहे।

उत्तरकाशी की बेटी पूजा परमार राणा : राष्ट्रपति भवन में सम्मानित

संवाददाता

नौगांव /उत्तरकाशी। जनपद उत्तरकाशी के लिए यह गर्व का क्षण है।अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन

में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया।यह सम्मान मिला श्रीमती पूजा परमार राणा को,सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नौगांव, उत्तरकाशी!15 वर्षों की अटूट सेवा ख़ हिमालय के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में उन गाँवों तक ख़ जहाँ पहुँचना भी आसान नहीं।कोविड-19 महामारी के दौरान यमुना नदी के तटवर्ती क्षेत्र में पहली वैक्सीनेटर के रूप में कार्य किया और शत-प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया।मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच हर मोर्चे पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई।जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने पूजा को बधाई देते हुए कहा कि पूजा जी आपकी यह उपलब्धि केवल आपकी नहीं।यह उत्तरकाशी की है।देव भूमि को आप पर गर्व है। जिला प्रशासन उत्तरकाशी की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।तथा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान सूर्यपाल रावत, क्षेत्र पंचायत सदस्य राजेश आदि ने भी पूजा को सम्मानित होने पर बधाई व शुभकामनायें प्रेषित की है!

सम्पादकीय

बंगाल में “शुभ राज”

पश्चिम बंगाल में 69 वर्षों के अथक संघर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार प्रथम सरकार शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में कार्यभार ग्रहण करके काम पर लग गयी है। बंगाल में बीजेपी की विजय बहुत बड़ी व ऐतिहासिक है। बंगाल ही नहीं भारत के अन्य भागों में भी इस विजय का आनंद दिखाई वातावरण दे रहा है। इस विजय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक, तेलंगना और गुजरात के दौरे में जो भीड़ उमड़ रही है उससे स्पष्ट रूप से जनसामान्य और भाजपा कायकर्ताओं के उत्साह का अनुमान लगाया जा सकता है। बंगाल विधानसभा चुनावों मे हिंदू समाज ने पहली बार बांग्लादेशी घुसपैठ और मुस्लिम तुष्टिकरण की विकृत राजनीति के विरुद्ध एकजुट होकर मतदान किया और जिसका परिणाम आज पूरा भारत देख रहा है। बंगाल की जिस धरती पर 75 वर्ष पूर्व डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की वैचारिक नींव रखी थी उसी बंगाल में पहली बार भाजपा 27 सीटों के साथ सत्ता के शिखर पर पंहुची और भगवा वस्त्रों में शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बंगाल की कैबिनेट में अभी पांच मंत्रियों को ही शपथ दिलाई गई है, जिसमें बंगाल में भाजपा का संगठन खड़ा करने में अहम भूमिका निभाने वाले दिलीप घोष, फैशन डिजाइनर से बंगाल भाजपा की सबसे मुखर नेत्री बनी अग्निमित्रा पॉल जिन्होंने तृणमूल के खिलाफ आक्रामक मोर्चा संभाला, बांग्लादेश के हिंदू शरणार्थी मतुआ समुदाय के प्रमुख चेहरे अशोक कीर्तनिया जो उत्तर 24 परगना जिले के भारत-बांग्लादेश सीमा से सटे इलाको में भाजपा के जमीनी संगठनकर्ता के रूप मे अत्यंत सक्रिय रहे हैं, छात्र राजनीति से उभरे नेता निशीथ प्रामाणिक जो 2019 में भाजपा से जुड़े और जंगल महल के आदिवासी समुदाय के बड़े नेता खुदीराम टुडू शामिल हैं। अभी इस मंत्रिमंडल है का विस्तार होना बाकी है। बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना के अनुरूप लघु भारत के भव्य दर्शन हो रहे थे तथा भविष्य की राजनीति के संकेत भी मिल रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आज तक बंगाल में कांग्रेस, वामपंथ और तृणमूल की सरकारें रहीं जो तुष्टिकरण में आकंठ डूबी रहीं और हिंदुओ को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया। स्थितियां इतनी विकट हो गयी थीं कि बंगाल की धरती पर जय श्रीराम बोलने पर नफरत का कहर टूट पड़ता था। आज उसी बंगाल में जब जयश्रीराम के नारे गूंज रहे हैं तो बंगाल का हर सनातनी खुशी से सराबोर हो रहा है। बंगाल में भाजपा सरकार आने से पश्चिम बंगाल के हिन्दुओं को तुष्टिकरण की दमनकारी नीतियों और भय के माहौल से आजादी मिली है। यह विजय केवल सत्ता का परिवर्तन नही अपितु बंगाल के पुनरुत्थान का शंखनाद है। अब बंगाल सही मायने में सोनार बांग्ला बनने की ओर अग्रसर होगा। भाजपा नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व आर्थिक उत्थान के नए दौर मे प्रवेश करेगा। हार की कुंठा से ग्रसित तृणमूल व विरोधी दलों के नेता अभी भी एसआईआर, चुनाव आयोग और केंद्रीय सुरक्षाबलों वाले आरोप दोहरा रहे हैं जबकि वास्तविकता यह है कि भाजपा ने यह चुनाव लम्बे संघर्ष और अपने कार्यकर्ताओं के बलिदान के बाद जीता है। तृणमूल के राज में वर्ष 2011 से 2025 के बीच भाजपा के 321 कार्यकर्ता मारे गए, उनके विरुद्ध हुई हिंसा में हजारों घर उजाड़ दी गए, भाजपा व संघ के किसी कार्यकर्ता को बम से उड़ाया गया किसी को पेड़ से लटकाया गया। 2021 में तो भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रति तृणमूल के लोगों ने क्रूरता की सभी सीमाएं लांघ दी थीं। नंदीग्राम से लेकर वीरभूम तक, कूच बिहार हो या वशीर हाट चुनाव के बाद बदले के नाम पर पूरे-पूरे गांव खाली करवा दिए गए थे। 2021 की चुनावी हिंसा में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए किंतु ममता सरकार उन सभी में अड़ंगा डालती रही। आज संदेशखाली से आर जी कर कांड तक सभी पीड़ित परिवारों के मन में एक नया सबेरा आया है कि अब न्याय होकर रहेगा।

सोमनाथ अमृत महोत्सव अगले एक हजार वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा है : प्रधानमंत्री

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लिया।

सोमनाथ मंदिर परिसर में इसकी पुनर्स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक भव्य सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस आयोजन को महज एक औपचारिक समारोह से कहीं अधिक, भारत की शाश्वत चेतना और सभ्यतागत दृढ़ता की घोषणा बताया। इस ऐतिहासिक सभा में वैदिक मंत्रों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और समुद्र की लहरों की गर्जना के संगम से दिव्य भक्ति और राष्ट्रीय गौरव का अद्भुत संगम देखने को मिला, जिसने इस पवित्र स्थल के पुनर्निर्माण का जश्न मनाया।

प्राचीन शास्त्रों के ज्ञान का हवाला देते हुए, प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे यह सृष्टि ईश्वर से उत्पन्न होती है और उसी में विलीन हो जाती है। श्री मोदी ने कहा, “यतो जायते पाल्यते येन विश्वम, तमिशम् भजे लीयते यत्र विश्वम्, आज हम उनके निवास के पुनर्निर्माण का पर्व मना रहे हैं।” अपनी व्यक्तिगत श्रद्धा व्यक्त करते हुए, प्रधानमंत्री ने दादा सोमनाथ के एक परम भक्त के रूप में मंदिर की अपनी अनगिनत यात्राओं को याद किया। श्री मोदी ने कहा, “मैंने उनके समक्ष अनगिनत बार नमन किया है, लेकिन आज जब मैं यहां आ रहा था, तो समय के इस सफर ने मुझे एक सुखद अनुभव दिया।”

प्रधानमंत्री ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान कुछ महीने पहले की अपनी हाल की यात्रा को याद करते हुए, दो समारोहों के एक साथ संपन्न होने के अनूठे महत्व पर प्रकाश डाला। श्री मोदी ने कहा, “प्रथम विनाश के 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ का अविनाशी रहना और आज इस आधुनिक स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष पूरे होने पर, हमें हजार वर्षों की अमर यात्रा का अनुभव करने का अवसर मिला है।”

1951 में हुए इस ऐतिहासिक प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कोई साधारण अवसर नहीं था। श्री मोदी ने कहा, ष्अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था, तो 1951 में सोमनाथ की प्राण-प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था।”

भारत की स्वतंत्रता के महज चार वर्ष बाद, 1951 में मंदिर के पुनर्निर्माण के गहन महत्व पर विचार करते हुए, प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा 500 रियासतों के राजनीतिक एकीकरण और सोमनाथ के पुनर्निर्माण के उनके दृढ़ संकल्प के बीच एक उल्लेखनीय समानता बताई। श्री मोदी ने कहा, ष्जब देश विदेशी गुलामी से मुक्त हुआ, तो सोमनाथ के पुनर्निर्माण ने एक साथ दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत न केवल स्वतंत्र हुआ है, बल्कि वह अपनी प्राचीन महिमा को पुनः प्राप्त कर रहा है।” इस अवसर के बहुआयामी महत्व को स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे केवल 75 वर्षों का पुनरावलोकन नहीं देख रहे हैं। श्री मोदी ने कहा, ष्मैं यहां सृजन और विनाश के उस संकल्प को देख रहा हूं, जिसे सोमनाथ ने पूरा किया है।ष उन्होंने पवित्र परिसर में असत्य पर सत्य की शाश्वत विजय को प्रत्यक्ष रूप से देखा। प्रधानमंत्री ने सदियों से चली आ रही आध्यात्मिक चेतना के साक्षी होने की बात कही, जिसने सार्वभौमिक कल्याण के पाठ प्रदान किए हैं। उन्होंने सोमनाथ की दृढ़ता में निहित भारत के अविनाशी सार के अपने दृष्टिकोण को व्यक्त किया। श्री मोदी ने कहा, ष्मैं यहां देख रहा हूं कि भारत का अविनाशी रूप, जिसे सदियों के क्रूर प्रयासों से मिटाया नहीं जा सका, पराजित नहीं किया जा सका।ष

उत्सव के दूरदर्शी आयाम पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत महोत्सव महज स्मरणोत्सव से कहीं बढ़कर है। श्री मोदी ने कहा, ष्यह केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि यह भारत के लिए आने वाले एक हजार वर्षों की प्रेरणा भी है।ष प्रधानमंत्री ने इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी देशवासियों और भगवान सोमनाथ के करोड़ों भक्तों को हार्दिक बधाई दी। राष्ट्रीय इतिहास के एक अन्य महत्वपूर्ण पड़ाव से इस दिन को जोड़ते हुए, उन्होंने सभा को याद दिलाया कि 11 मई को भारत द्वारा 1998 में पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षणों की वर्षगांठ भी मनाई जाती है। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे देश ने 11 मई को तीन परमाणु परीक्षण किए, जिससे भारतीय वैज्ञानिकों की क्षमता का प्रदर्शन हुआ। उन्होंने 13 मई को किए गए बाद के परीक्षणों को भारत के अटूट राजनीतिक संकल्प के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया। श्री मोदी ने कहा, ष्उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में तत्कालीन सरकार ने यह प्रदर्शित किया कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, दुनिया की कोई भी शक्ति भारत को झुका नहीं सकती या उस पर दबाव नहीं डाल सकती।”ऑपरेशन के नाम के महत्व को समझाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पोखरण परमाणु परीक्षण को श्ऑपरेशन शक्तिश नाम देने के पीछे गहरे सांस्कृतिक कारण हैं। श्री मोदी ने कहा, ष्क्योंकि शिव के साथ शक्ति की पूजा करना हमारी परंपरा रही है।ष हिंदू प्रतिमा विज्ञान का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि अर्धनारीश्वर शिव, शिव और शक्ति की अविभाज्यता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि जब भारत का चंद्रयान मिशन सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरा था, तब भी इसी दर्शन के अनुसार लैंडिंग स्थल का नाम रखा गया था। व्युत्पत्ति संबंधी जुड़ाव पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने प्राचीन ज्ञान और आधुनिक उपलब्धि के संगम पर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा, ष्यह कितना सुखद है कि इस ज्योतिर्लिंग को चंद्रमा (सोम) के नाम पर सोमनाथ कहा जाता है।ष्प्रधानमंत्री ने बताया कि शिव और शक्ति की एक साथ पूजा करने का दर्शन अब भारत की वैज्ञानिक प्रगति को प्रेरित कर रहा है। श्री मोदी ने कहा, ष्आज हम इस संकल्प को साकार होते देख रहे हैं कि शिव और शक्ति की हमारी पूजा देश की वैज्ञानिक प्रगति के लिए प्रेरणा बने।ष उन्होंने ऑपरेशन शक्ति की वर्षगांठ पर सभी देशवासियों को बधाई दी।

प्रधानमंत्री ने मंदिर के हजार साल के विनाश और पुनर्निर्माण के बारे में बताते हुए इस इतिहास को जीवंत करने वाली अदम्य भावना पर प्रकाश डाला। महमूद गजनी और अलाउद्दीन खिलजी जैसे आक्रमणकारियों के लगातार हमलों के बावजूद, मंदिर का पुनर्निर्माण राजा भोज, भीमदेव प्रथम, कुमारपाल, महिपाला प्रथम और राव खंगर जैसे समर्पित शासकों द्वारा बार-बार किया गया, जिनमें से प्रत्येक ने एक प्रबल आध्यात्मिक आह्वान का जवाब दिया। श्री मोदी ने कहा, “जिन्होंने विनाश किया, उन्होंने केवल पत्थर और गारा देखा, लेकिन वे हमारी सभ्यता की बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति को कभी नहीं समझ पाए।ष्देश के सांस्कृतिक पुनरुद्धार पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने क्षेत्र की पवित्र विरासत को संरक्षित करने वाले संत लकुलिशा और सोम शर्मा जैसे प्रख्यात विद्वानों के योगदान को स्वीकार किया। उन्होंने भव बृहस्पति, पशुपतचार्यों और कई अन्य विद्वानों के विद्वतापूर्ण योगदान को भी सराहा, जिन्होंने क्षेत्र की आध्यात्मिक परंपराओं को कायम रखा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विशालदेव और त्रिपुरंतक जैसे बुद्धिजीवियों को भी सम्मानित किया, जिन्होंने क्षेत्र की चेतना की रक्षा की। सम्मान के दायरे को बढ़ाते हुए, उन्होंने वीर हमीरजी गोहिल, वीर वेग्दाजी भील, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर जी, बड़ौदा के गायकवाड़, जाम साहब महाराजा दिग्विजय सिंह जी जैसे कई अन्य महान व्यक्तित्वों के बारे में भी चर्चा की, जिन्होंने सोमनाथ की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने विशेष रूप से सोमनाथ की पुनर्स्थापना के आधुनिक निर्माताओं जैसे सरदार पटेल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी जी और ऐसे सभी दिव्य आत्माओं को नमन किया। उन्होंने समकालीन जिम्मेदारी के लिए उनकी विरासत से प्रेरणा ली। श्री मोदी ने कहा, ष्उनकी स्मृति हमें प्रेरित करती है कि हमें न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, बल्कि इस जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों के हाथों में भी सौंपना है।ष भारत की विशाल सांस्कृतिक विरासत पर विचार करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि सांस्कृतिक स्थल हजारों वर्षों से राष्ट्र की पहचान रहे हैं। फिर भी उन्होंने स्वतंत्रता के बाद के भारत में एक दुखद विडंबना की ओर इशारा किया।

राज्यपाल ने किया उत्कृष्ट कार्य करने वाले नर्सिंग अधिकारियों को सम्मानित

संवाददाता

देहरादून/ऋषिकेश। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने मंगलवार को एम्स ऋषिकेश में आयोजित "उन्नत ट्रॉमा देखभाल, अंगदान और नर्सिंग उत्कृष्टता" विषयक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नर्सिंग अधिकारियों को सम्मानित किया तथा अंगदान करने वाले दानदाताओं एवं उनके परिजनों को भी सम्मान प्रदान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि ट्रॉमा केयर, अंगदान और नर्सिंग उत्कृष्टता केवल चिकित्सा विज्ञान के विषय नहीं हैं, बल्कि मानवता की रक्षा के तीन सशक्त स्तंभ हैं। ये सेवा-भाव, संवेदनशीलता और जीवन के प्रति उत्तरदायित्व का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि नर्सिंग सेवा करुणा, समर्पण और मातृत्व की भावना का जीवंत स्वरूप है। गंभीर अवस्था में मरीज के लिए नर्स केवल स्वास्थ्यकर्मी नहीं, बल्कि विश्वास, सहारा और आत्मीयता का प्रतीक बन जाती है।

राज्यपाल ने नर्सिंग पेशे के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा कि नर्सें समाज में मानव सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। ट्रॉमा प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए राज्यपाल ने कहा कि दुर्घटना के बाद का "गोल्डन ऑवर" अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और समय पर उपचार मिलने से मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड जैसे दुर्गम एवं पर्वतीय राज्य में प्रभावी ट्रॉमा प्रबंधन की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। अंगदान के महत्व पर बल देते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह मानवता का सर्वोच्च दान है, जो किसी व्यक्ति को नया जीवन प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि शरीर भले ही नश्वर हो, लेकिन दान किए गए अंग मानवता के साथ जीवित रहते हैं। उन्होंने समाज से अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे अनेक लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। राज्यपाल ने प्रसन्नता व्यक्त की कि एम्स ऋषिकेश हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस, टेलीमेडिसिन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तथा ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रभावी उपयोग कर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बना रहा है।

उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में एआई आधारित तकनीकों, रोबोटिक्स, आधुनिक डायग्नोस्टिक्स, नेत्र चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों की भी प्रशंसा की। इस अवसर पर मेयर ऋषिकेश श्री शंभू पासवान, अध्यक्ष राज्य महिला आयोग श्रीमती कुसुम कण्डवाल, एम्स की कार्यकारी निदेशक डॉ. मीनू सिंह, एचओडी ट्रॉमा केयर डॉ. कमर आजम, डॉ. शैलेन्दु शंकर, कर्नल बीनू शर्मा, डॉ. मधुर उनियाल सहित एम्स ऋषिकेश के मेडिकल स्टाफ एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

पद्मविभूषण सुर स्वामिनी आशा भोसले जी को संगीतमय श्रधांजलि व मातृ शक्ति सम्मान

संवाददाता

देहरादून। अखिल भारतीय देवभूमि ब्राह्मण जन सेवा समिति, शैल शिखर सामाजिक संस्था ,गोपाल संगीत मंच समिति ,श्रीमती सोनिया आनंद रावत व पंडित ज्योति प्रसाद शर्मा फाउंडेशन द्वारा ब्राह्मण गौरव पद्मविभूषण सुर स्वामिनी आशा भोसले जी को दिनांक 10-5-2026 रविवार को होटल एलीट पटेल नगर देहरादून में संगीतमय श्रधांजलि प्रदान की गई।

देर शाम तक चले कार्यक्रम में देवभूमि की प्रख्यात गायिका श्रीमती सोनिया आनंद रावत जी ने ,श्री रविन्द्र सिंह आनंद जी ने , पत्रकार श्री बालेश कुमार गुप्ता जी ने ,श्री राजेश शर्मा जी ने ,श्री प्रदीप गुप्ता जी ने सुरों के माध्यम से आशा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करे। तथा

पूजा राठौर ने मधुर भजन,सावला सलोना,चलो बुलवा आया है व पिया अब तो आजा ,ओ मेरे सोना रे सोना आदि गीत व भजनों के माध्यम से आशा जी को श्रद्धांजलि दी।गोपाल संगीत मंच व गुरुकुल के छात्रों वृंदा मेनी, अराना, नव्या, त्रिशिका ,चित्रांशी उर्वी, मंजप ,वंशिका ,मनमीत कौर ने राधा कैसे न जले ,पिया बांवरी जैसे शास्त्रीय संगीत से संबंधित गीत पर नृत्य कला की प्रतिभा का प्रदर्शन कर आशा जी को श्रद्धांजलि दी। तेजस्वी,अनामिका , अवन्या आदि बालिकाओं ने मेरा नाम चिन चेन चू, झुमका गिरा रे आदि मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए। पंडित ज्योति प्रसाद फाउंडेशन व शैल शिखर सामाजिक संस्था में माध्यम से गीत व नृत्य की प्रस्तुति देने वाले छात्रों/बच्चों को उपहार प्रदान कर उनका सम्मान किया गया।अंतराष्ट्रीय मदर डे के अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित समस्त मातृ शक्ति को अंगवस्त्र प्रदान कर उनका स्वागत व सम्मान समिति द्वारा किया गया ।श्रधांजलि सभा का संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष अरुण कुमार शर्मा ने कहा की ब्राह्मण गौरव आशा जी अद्भभुत कला की धनी थी माँ सरस्वती का विशेष स्नेह उन्हें प्राप्त था अपनी मेहनत व समर्पण से आशा जी ने माँ सरस्वती की सेवा करते हुए संगीतजगत में सम्पूर्ण विश्व मे भारत देश का सम्मान बढ़ाया। आशा जी की एक विशेषता यह थी की उनकी आवाज हर कलाकार पर ऐसी प्रतीत होती थी जैसे वह कलाकार स्वंय गीत गा रही है। कलाकार की आदत व अभिनय के अनुरूप अपनी आवाज का उपयोग करना आशा जी बखूबी जानती थी युगों युगों में ऐसे प्रतिभावन लोग इस धरा पर जन्म लेते है। जब तक इस धरा पर जीवन है आशा जी तब तक लोगों के हृदय में रहेंगी।समिति के संरक्षक श्री पवन शर्मा जी ,श्रीमती आभा बड़थवालं जी ,श्रीमती रेणु शर्मा जी ने सभा को संबोधित करते हुए आशा जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए।आज के कार्यक्रम में नागरिक सुरक्षा संगठन (सिविल डिफेंस) की पोस्ट संख्य 4 दक्षिण प्रभाग के समस्त वार्डनों ने कार्यक्रम में उपस्थित हो अपना सहयोग प्रदान किया। आज के कार्यक्रम में समिति की सचिव रुचि शर्मा,प्रदेश मीडिया प्रभारी अनुराग गौड,प्रदेश महासचिव डॉ अजय वशिष्ठ ,सचिव संजय मिश्रा ,विचित्र शर्मा महानगर देहरादून अध्यक्ष राजेश पंत ,एडवोकेट राजगीता शर्मा डॉ रचना शर्मा,सुशीला शर्मा,वासु वशिष्ठ,वसुधा,रमेश मिश्रा,शशि शर्मा,राजकुमार शर्मा,मनीष शर्मा,निशा शर्मा,बीना अग्रवाल ,मधु शर्मा ,भारती जोशी ,विद्या भारद्वाज ,जय कुमार भारद्वाज,राजेश भारद्वाज,अभिषेक ,दीपाली,कल्याण,उषा राजपूत मीनू शर्मा प्रमोद शर्मा ,रामगोपाल शर्मा,विक्रम शर्मा आदि तथा विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि सम्मलित रहे।

सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता से करे संबंधित अधिकारी

हरिद्वार। जनपदवासियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें

विभिन्न विभागों से संबंधित 66 शिकायते दर्ज कराई गई,जिसमें से 30 समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया शेष समस्याओं को निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया। जनसुनवाई कार्यक्रम में राजस्व, भूमि, विवाद, विद्युत, अतिक्रमण,जल भराव, पेयजल आदि से संबंधित समस्या दर्ज कराई गईजनसुनवाई कार्यक्रम में शिकायतकर्ता सुमन देवी, ज्योति देवी एवं राजन देवी निवासी ग्राम लालढांग की भूमि जिसका खसरा नं 237 है, भूमि के पास में ही बस्ती के कुछ लोगों ने उनकी भूमि में अवैध कब्जा कर और खेत में नाली का पानी डाला हुआ है, उन्होंने कब्जा हटवाने एवं नाले के पानी का निस्तारण करवाने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थी मांगेराम एवं राजवीर निवासी गंगदासपुर तहसील लक्सर ने ग्राम गंगदासपुर का बाढ़ग्रस्त होने के कारण प्रार्थी को फेरूपुर कठिया में विस्थापित किया गया था, उस जमीन पर गांव के कुछ व्यक्ति कब्जाने के प्रयास कर रहे है, उन्होंने भूमि की पैमाईश कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया।प्रार्थी दिनेश कुमार की भूमि जिसका खसरा नं 221, खतौनी संख्या 349, रकबा 0.092 है जो अतमलपुर बोगला परगना ज्वालापुर में स्थित है,प्रार्थी ने दोबारा आबादी दर्ज किए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया।प्रार्थी मुकेश कुमार निवासी मीरपुर ब्लॉक बहादराबाद द्वारा बताया गया कि पडोस के कुछ लोगों ने अपने घरों का गंदा पानी प्रार्थी के घर के आगे छोड़ रखा है,जिस कारण बच्चों को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है,इस समस्या के निदान के लिए प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थी कमल देवी सुमन नगर ने अपने आवासीय प्लाट जो कि सुमन नगर में स्थित है उसकी खतौनी की नकल दिलवाए जाने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया।

डेंगू रोकथाम कार्ययोजना की क्रियान्वयन पर विभागों की भूमिका पर की चर्चा

संवाददाता

रुद्रप्रयाग। डेंगू रोग रोकथाम व नियंत्रण हेतु जिला स्तरीय अंतरविभागीय बैठक में जिलाधिकारी द्वारा डेंगू रोकथाम की कार्ययोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को मजबूत समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। एनआईसी सभागार में जिलाधिकारी विशाल मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आयोजित अंतरविभागीय बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, नगर पालिका, सिंचाई, परिवहन आदि विभागों द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिलाधिकारी द्वारा डेंगू नियंत्रण को लेकर सभी संबंधित विभागों को अपने-अपने क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित कार्य अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी आरएस रावत ने मच्छर पनपने वाले स्थानों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाने पर जोर दिया।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राम प्रकाश ने बताया कि डेंगू रोग रोकथाम व नियंत्रण के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर स्तर पर तैयारियां की गई हैं, जिसके अंतर्गत ब्लाक स्तर पर कार्ययोजना तैयार कर दी गई है। उन्होंने शिक्षा एवं बाल विकास विभाग से स्कूल, आंगनबाड़ी में डेंगू से बचाव के बारे में जागरूकता फैलाने, पेयजल निगम व जलसंस्थान से पाइप लाइन से लिकेज आदि का अनावश्यक पानी जमा न होने देने, नगर पालिका व नगर पंचायतों से उनके क्षेत्र में अनावश्यक पानी जमा न होने देने, नियमित फॉगिंग कराते रहने, पंचायतीराज विभाग से ग्राम स्तर पर डेंगू जागरूकता को लेकर जनमानस को जागरूक करने, परिवहन विभाग से मैदान से आवागमन करने वाले सब्जियों के वाहक ट्रक आदि वाहनों में रखे टायरों में पानी जमा होने व उनके माध्यम से डेंगू का मच्छर आने की आशंका के दृष्टिगत संबंधित को संवेदीकृत करने की अपील की।

एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉ. शाकिब हुसैन ने कहा कि रुके हुए पानी में डेंगू का मच्छर पनपने की आशंका बनी रहती है, लिहाजा डेंगू से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि डेंगू के मच्छर को पनपने ही न दें, इसके लिए घरों, स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों के आस-पास पानी एकत्रित न होने दें, उन्होंने जल भंडारण की वस्तुओं को ढक कर रखने, कूलर, फूलदान, टंकी आदि ऐसी चीजें जहां पानी एकत्र हो सकता है वहां पानी एकत्र न होने दें व इन स्थानों पर सप्ताह में एक बार सफाई करने तथा डेंगू के मच्छर से बचाव हेतु पूरी बांहों वाले कपड़े पहनने, मच्छरदानी, मच्छर नाशक क्रीम, स्प्रे आदि का प्रयोग करने की अपील की है।

इस अवसर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी अजय कुमार चौधरी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सीमा टेकचंदानी, परिवहन विभाग से एआरटीओ धर्मेंद्र बिष्ट, ईओ नगर पालिका रुद्रप्रयाग हरेंद्र सिंह, ईओ नगर पंचायत अगस्त्यमुनि निकिता भट्ट, एई राजन कुमार आदि मौजूद रहे।

16 आईशोलेशन बार्ड बनाए, जांच किट पर्याप्त उपलबध :- मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राम प्रकाश ने बताया कि डेंगू रोग रोकथाम के तहत सीएचसी अगस्त्यमुनि में 6, सीएचसी जखोली, पीएचसी ऊखीमठ में 02-02, माधवाश्रम चिकित्सालय में 06 आईशोलेशन वार्ड सहित कुल 16 आइसोशलन वार्ड बनाए गए हैं व वार्ड नोडल की तैनाती भी कर दी गई है।

बताया कि डेंगू जनपद में पर्याप्त मात्रा में डेंगू जांच किट उपलब्ध है। ब्लाकों को डेंगू किट उपलब्ध कराई गई है।

16 मई से चलेगा अभियान :- मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रामप्रकाश ने बताया कि डेंगू रोग रोकथाम एवं नियंत्रण को लेकर 16 मई से स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत स्वास्थ्य उपकेंद्र व हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एएनएम और सीएचओ द्वारा जागरूकता गतिविधियां की जाएंगी।

आशा कार्यकत्री द्वारा लार्वा निरोधात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसके तहत डेंगू मच्छर पनपने वाले संभावित स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाकर डेंगू मच्छर के लार्वा को खत्म करने की कार्यवाही की जाएगी।

अशासकीय विद्यालयों का वेतन शीघ्र जारी होगा: डॉ. धन सिंह रावत

संवाददाता

देहरादून। प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों को तीन महीने से वेतन नहीं मिलने पर विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह ने विभागीय अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई कर लंबित वेतन शीघ्र जारी करने के निर्देश दिये, साथ ही उन्होंने भविष्य में ऐसी लापरवाही न दोहराने की हिदायत भी अधिकारियों को दी।

डॉ. रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षकों एवं कर्मचारियों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी भी शिक्षक एवं कर्मचारी को अनावश्यक आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े इसके लिये सभी लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण कड़ी है और सरकार उनके सम्मान एवं सुविधाओं के प्रति प्रतिबद्ध है। डॉ. रावत ने स्पष्ट किया कि अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान में आ रही बाधाओं को शीघ्र दूर कर नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि संबंधित विद्यालयों एवं विभागीय स्तर पर लंबित औपचारिकताओं को तेजी से पूरा कर यथाशीघ्र वेतन निर्गत किया जाए, ताकि शिक्षकों एवं कर्मचारियों को राहत मिल सके। वहीं अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने विभागीय मंत्री डॉ. धन सिंह रावत द्वारा प्रकरण का संज्ञान लिये जाने तथा शीघ्र वेतन अहरण के निर्देश दिये जाने पर उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि राजकीय शिक्षकों की भांति अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का कर्मचारियों का वेतन समय पर अहरण किया जाय।

विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने समाचार पत्रों में प्रकाशित उत्तरकाशी जनपद के मोरी विकासखंड स्थित ओसला गांव में विद्यालय भवन न होने संबंधी खबर का गंभीरता से संज्ञान लिया है। समाचारों में दावा किया गया था कि ओसला गांव में विद्यालय का भवन पिछले 15 वर्षों से निर्मित नहीं हो पाया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।

उक्त प्रकरण के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), उत्तरकाशी द्वारा जिलाधिकारी को प्रेषित रिपोर्ट में बताया गया है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय ओसला में वर्तमान में 24 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं और विद्यालय भवन अच्छी स्थिति में संचालित हो रहा है। वहीं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ओसला में वर्तमान में केवल 1 छात्र अध्ययनरत है। छात्रहित को ध्यान में रखते हुए दोनों विद्यालयों का संचालन राजकीय प्राथमिक विद्यालय ओसला भवन में किया जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ओसला के भवन मरम्मत एवं रंग-रोगन हेतु जिला योजना के अंतर्गत रु0 3.50 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई थी, किन्तु कार्यदायी संस्था द्वारा धनराशि को अपर्याप्त बताया गया।

21 से 23 अगस्त तक उच्चतम न्यायालय में आयोजित होगा 'समाधान समारोह'

संवाददाता

देहरादून। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून की सचिव एवं सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) सीमा डुंगरकोटी ने जानकारी देते हुए बताया कि उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में 21, 22 एवं 23 अगस्त 2026 को "समाधान समारोह"के अंतर्गत विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस विशेष लोक अदालत में उच्चतम न्यायालय में लंबित विभिन्न प्रकार के वादों का आपसी सुलह एवं राजीनामे के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। इनमें फौजदारी मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस मामले, बैंक ऋण एवं वसूली संबंधी मामले, दीवानी एवं वैवाहिक वाद, बीमा दावे, सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित प्रकरण, शैक्षणिक एवं सेवा संबंधी मामले सहित अन्य प्रकृति के वाद शामिल हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने बताया कि जिन वादकारियों के मामले माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं तथा जो अपने मामलों का शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण समाधान चाहते हैं, वे 20 अगस्त 2026 तक अपने मामलों को आवश्यक रूप से उच्चतम न्यायालय में सूचीबद्ध करा लें। उन्होंने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत देहरादून जनपद से संबंधित उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों के पक्षकारों को नोटिस भेजकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में प्री-मीटिंग एवं सुलह वार्ता हेतु आमंत्रित किया जा रहा है। वार्ता सफल होने पर संबंधित मामलों को विशेष लोक अदालत में निस्तारित कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही प्राधिकरण के सहयोग से की जाएगी। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने समस्त वादकारियों से अपील की है कि वे अपने लंबित मामलों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क करें।

सोने की खरीद पर प्रतिबंध लगाने से पड़ सकता है रोजगार पर असर

देहरादून। सोने के आभूषणों की खरीद में कमी से 1 करोड़ से अधिक लोगों की नौकरियों पर असर पड़ सकता है। अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की खरीद कम करने की अपील का असर आभूषण उद्योग से जुड़े 1 करोड़ से अधिक लोगों की नौकरियों पर पड़ सकता है। यह चिंता व्यक्त की गई है कि सोने के आभूषणों की मांग घटने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रभावित हो सकते हैं। जीजेसी के अनुसार, यह फैसला उद्योग में तनाव पैदा कर सकता है और 1 करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका को सीधे प्रभावित कर सकता है। यह प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री की पश्चिम एशिया संकट और विदेशी मुद्रा भंडार के दबाव के बीच सोने की खरीद कम करने की अपील के बाद आई है। जीजेसी ने सोने की खपत कम करने के बजाय, घर में रखे सोने को मौद्रिकरण के माध्यम से उपयोग करने का सुझाव दिया है। इस बयान के बाद शेयर बाजार में आभूषण कंपनियों के शेयरों में दबाव देखा गया, जिसमें कल्याण ज्वैलर्स और पीएनजी ज्वैलर्स जैसे शेयरों में गिरावट दर्ज की गई।

कैफी आजमी के लिखे गीतों को मिली सराहना

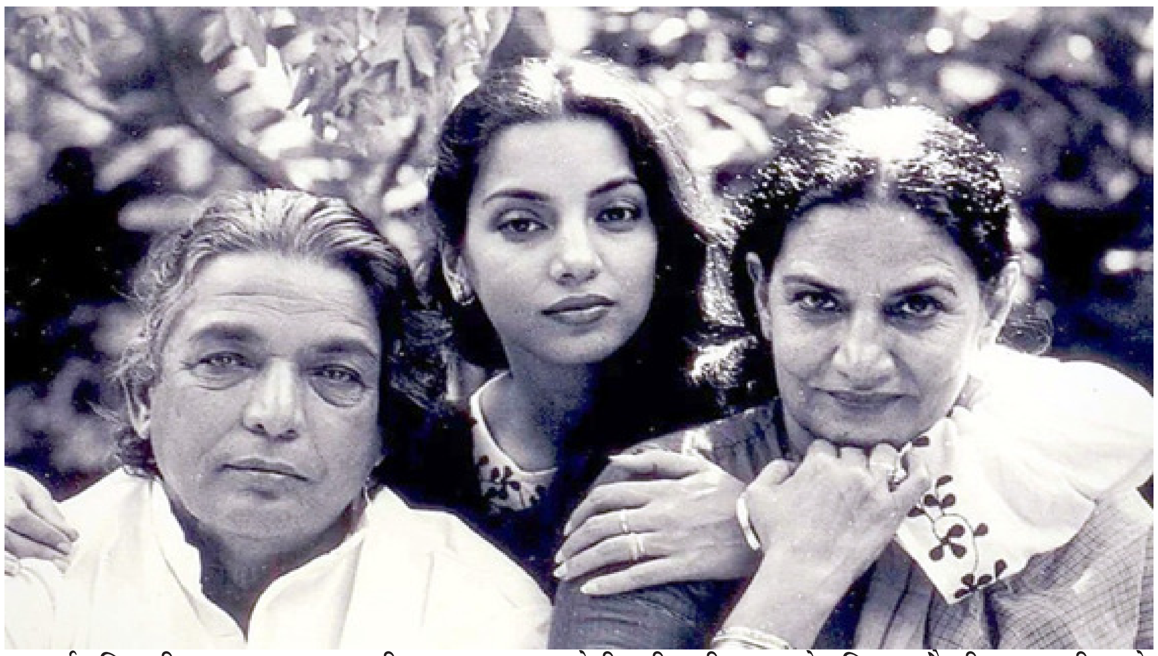

नई दिल्ली। शबाना आजमी तब बहुत छोटी ही थी। अपने पिता कैफी आजमी को देखकर वो बड़ा हैरान होती थी। उन्हें बड़ा अजीब लगता था कि उनके पिता सफेद कुर्ता-पजामा पहनते हैं। जबकी दूसरे लोग पैंट-शर्ट पहनते हैं। उस वक्त शबाना ये भी सोचा करती थी कि उनके पिता घर पर बैठे लिखते हमेशा लिखते ही क्यों रहते हैं? वो कभी ऑफिस क्यों नहीं जाते हैं? शायद उनके पिता को कोई और काम नहीं आता है। मगर एक दिन जब कैफी आजमी का नाम अखबारों में छपा तो शबाना की स्कूल की दोस्तों ने इन्हें बताया कि तुम्हारे पिता का नाम अखबारों में छपा है। उस दिन शबाना बहुत खुश हुई। उन्होंने मान लिया कि उनके पिता दूसरों से बहुत अलग हैं। आज कैफी आजमी साहब की पुण्यतिथि है। हिंदी सिनेमा को कई खूबसूरत गीत देने वाले कैफी आजमी साहब 10 मई 2002 को ये दुनिया छोड़कर चले गए थे। एक इंटरव्यू में कैफी साहब ने कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें उस दिन कुछ समझना शुरू किया था जब महान गुरूदत्त साहब ने उन्हें पहली दफा साइन किया था। सब मान गए कि अगर गुरूदत्त ने साइन किया है तो इसका मतलब इस शायर में कोई बात है। वो फिल्म थी कागज के फूल, जो गुरूदत्त के जीवन से ही प्रेरित थी। उस फिल्म के सभी गीत कैफी आजमी ने लिखे थे। सिवाय एक को छोड़कर। उस फिल्म का एक गीत शैलेंद्र जी ने लिखा था। दुर्भाग्यवश कागज के फूल फ्लॉप हो गई। कागज के फूल फ्लॉप क्या हुई, कैफी आजमी को भी प्रोड्यूसर्स ने नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। कुछ संगीतकार तो उस वक्त ऐसे भी थे जो कहने थे कि ये आदमी तो मनहूस है। इसके साथ काम करके कौन नुकसान उठाएगा। कागज के फूल साइन करते वक्त कहां तो कैफी आजमी को लग रहा था कि अब उनके दिन बदलने वाले हैं। लेकिन फिल्म के फ्लॉप होने के बाद उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई थी। एक वक्त था जब शौकत कैफी और कैफी आजमी शादी करने का इरादा कर चुके थे तब शौकत कैफी के पिता इनकी शादी नहीं होने देना चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी बहुत खर्चीली है। उसने कभी अभावों की जिंदगी नहीं देखी। वो इस बहुत कम कमाने वाले लड़के के साथ कैसे खुश रह सकती है। लेकिन शौकत कैफी ने अपने पिता व परिवार के किसी दूसरे इंसान की नहीं सुनी। उन्होने कैफी आजमी से शादी की। इसिलिए जब कागज के फूल फिल्म फ्लॉप होने के बाद कैफी आजमी जबरदस्त मुश्किलों में घिरे तब शौकत कैफी ने उन मुश्किलों में कैफी साहब का पूरा साथ दिया। यूं तो कागज के फूल से पहले भी कैफी साहब ने कुछ फिल्मों के गीत लिखे थे। लेकिन उन फिल्मों से इन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिल सकी थी। कागज के फूल फ्लॉप हुई तो चुनौतियां और कई गुना बढ़ गई। उसके बाद भी कुछ फिल्में कैफी आजमी जी को मिली थी। जिनमें से एक थी धर्मेंद्र जी की शोला और शबनमन। लेकिन सही मायनों में कैफी आजमी को सफलता का स्वाद चखाया 1964 में चेतन आनंद की हकीकत ने। जब चेतन आनंद ने हकीकत के लिए कैफी आजमी को साइन किया था तब कुछ लोगों ने चेतन को कहा था कि आप कैफी आजमी को ना साइन करें। उसके तो सितारे ही अच्छे नहीं चल रहे हैं। चेतन आनंद ने उन लोगों को जवाब दिया कि सितारे तो इन दिनों मेरे भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो क्या पता, हम दो खराब सितारों वाले मिलकर शायद कुछ अच्छा कर लें। हकीकत बनी और रिलीज हुई। फिल्म की कहानी के साथ-साथ कैफी आजमी के लिखे गीतों को भी खूब सराहना मिली। और कैफी साहब के खराब सितारों की बात करने वाले लोगों की जुबान पर ताला लग गया।

राजस्थान के कुचामन शहर में हुआ था राजश्री के संस्थापक ताराचंद बड़जात्या का जन्म

नई दिल्ली। रामू और मोहन की सच्ची दोस्ती ना दिखती। राम और मालती की हंसी-ठिठोली भी ना होती। होते ना ताराचंद तो गुंजा और चंदन का पवित्र पवित्र प्रेम भी कहां होता। आज राजश्री के संस्थापक ताराचंद बड़जात्या जी का जन्मदिवस है। 10 मई 1914 को राजस्थान के कुचामन शहर में ताराचंद जी का जन्म हुआ था। शिक्षा हुई कलकत्ता के विद्यासागर कॉलेज में। 19 साल की छोटी सी उम्र में ही ताराचंद बड़जात्या ने बड़े ख्वाब देखने शुरू क दिए थे। कोलकाता में ही फिल्मी दुनिया से जुड़े और इस दुनिया को बहुत करीब से देखा। फिल्में कैसे बनती हैं, ये सीखा। और 15 अगस्त 1947 को जब भारतवर्ष ने एक नई सुबह देखी, उसी दिन ताराचंद बड़जात्या ने स्थापित किया राजश्री पिक्चर्स। उस वक्त राजश्री पिक्चर्स एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी। सूरज बड़जात्या ने अपनी बेटी राजश्री के नाम से अपनी कंपनी की शुरुआत की थी। बेटी राजश्री का जन्म उसी साल हुआ था। उस जमाने में साउथ की कई बड़ी फिल्म मेकिंग कंपनी थी जो हिंदी फिल्मों का भी निर्माण करती थी। उनमें प्रमुख थी प्रसाद पिक्चर्स, एवीएम और जैमिनी।

अपनी कंपनी राजश्री पिक्चर्स के अंडर में ताराचंद बड़जात्या साउथ की इन कंपनीज की हिंदी फिल्मों को पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट और प्रदर्शित किया करते थे। इनमें से अधिकतर वो फिल्में थी जो पारिवारिक और साफ-सुथरी हुआ करती थी। एक दिन ताराचंद बड़जात्या जी ने सोचा कि क्यों ना वो खुद भी ऐसी ही पारिवारिक फिल्मों का निर्माण करें। और इस तरह 1962 में स्थापित हुआ राजश्री प्रोडक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड। अपने बैनर राजश्री प्रोडक्शन्स के अंडर में ताराचंद ने जो पहली फिल्म बनाई थी उसका नाम था आरती। 1962 में ही आरजी रिलीज हुई थी। आरती में मीना कुमारी, अशोक कुमार व प्रदीप कुमार जैसे दिग्गज कलाकार थे। फिर 1964 में वो फिल्म आई जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में तहलका ही मचा दिया। वो फिल्म थी दोस्ती, जिसके गीतों ने दर्शकों के दिलों को जीत लिया। उसी साल राज कपूर की अति महत्वकांक्षी फिल्म संगम भी रिलीज हुई थी। लेकिन दोस्ती ने संगम को हर मोर्चे पर कड़ी टक्कर दी। दोस्ती फिल्म की जबरदस्त कामयाबी ने राजश्री प्रोडक्शन को फिल्म इंडस्ट्री की टॉप फिल्म कंपनीज की कतार में ला खड़ा किया। ताराचंद जी की हिम्मत को सभी ने सैल्यूट किया। क्योंकि दोस्ती में उन्होंने किसी स्टार फेस को कास्ट नहीं किया था। बल्कि दो नए लड़कों के भरोसे पूरी फिल्म का निर्माण किया गया था। और फिल्म बहुत कामयाब रही।ताराचंद बड़जात्या जी ने आगे चलकर तकदीर, जीवन मृत्यु, उपहार, मेरे भईया, पिया का घर, सौदागर (1973) जैसी फिल्मों का निर्माण किया। इनकी फिल्मों की खासियत थी उनका पारिवारिक कंटेंट और बिना किसी फूहड़ता वाले दृश्य। चूंकि ताराचंद जी साहित्य के बड़े शौकीन थे तो उनकी फिल्मों में साहित्यिक कथानक भी यदा-कदा नजर आ जाते थे।

गहरे समुद्र के नीचे पाइपलाइन बिछवाने जा रहे हैं मोदी

संकट और चुनौतियों का डटकर सामना करने तथा उनसे मिले अनुभवों के आधार पर आगे के लिए पुख्ता तैयारी करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई जवाब नहीं। पश्चिम एशिया में ईरान युद्ध के बाद पैदा हुए तनाव और होरमुज जलडमरूमध्य में ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने के चलते भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर जो सबसे महत्वाकांक्षी कदम उठाया है, वह दर्शाता है कि प्रधनमंत्री मोदी कितनी दूरदर्शिता रखते हैं। हम आपको बता दें कि मोदी सरकार करीब 40 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली एक विशाल गहरे समुद्र की गैस पाइपलाइन परियोजना को तेजी से आगे बढ़ा रही है, जिसका उद्देश्य आने वाले कई दशकों तक देश में गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है। यह परियोजना केवल ऊर्जा सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि बदलते वैश्विक हालात में भारत की दूरदर्शी कूटनीति और रणनीतिक सोच का भी प्रतीक मानी जा रही है।दरअसल, भारत अपनी तेल और गैस जरूरतों के लिए लंबे समय से खाड़ी देशों पर निर्भर रहा है। होरमुज जलडमरूमध्य को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा गलियारा माना जाता है, जहां से एशिया और यूरोप तक तेल और गैस की भारी आपूर्ति होती है। लेकिन ईरान युद्ध और अमेरिका तथा इजराइल के साथ बढ़े तनाव के कारण इस मार्ग पर संकट गहरा गया। फरवरी में ईरान की ओर से इस मार्ग पर प्रभावी रोक लगाए जाने से वैश्विक तरल प्राकृतिक गैस आपूर्ति में 20 प्रतिशत से अधिक गिरावट आई और अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस कीमतों में तेज उछाल देखा गया। भारत की दो तिहाई तरल प्राकृतिक गैस आपूर्ति इसी मार्ग से आती रही है, इसलिए नई दिल्ली के लिए यह संकट

एक गंभीर चेतावनी साबित हुआ।इसी पृष्ठभूमि में भारत सरकार ने ओमान से सीधे गुजरात तक गहरे समुद्र के नीचे पाइपलाइन बिछाने की योजना को प्राथमिकता दे दी है। प्रस्तावित मध्य पूर्व भारत गहरे समुद्र पाइपलाइन परियोजना लगभग दो हजार किलोमीटर लंबी होगी और अरब सागर के नीचे से गुजरते हुए ओमान को सीधे गुजरात तट से जोड़ेगी। इस पाइपलाइन के जरिये प्रतिदिन लगभग 31 मिलियन मानक घन मीटर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति संभव होगी। परियोजना का मार्ग इस तरह तैयार किया जा रहा है कि यह भू राजनीतिक रूप से संवेदनशील इलाकों से बचते हुए ओमान और संयुक्त अरब अमीरात के रास्ते भारत तक पहुंचे।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद भारत को ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कतर जैसे गैस संपन्न देशों के विशाल भंडार तक सीधी पहुंच मिल सकेगी। इन देशों के पास मिलाकर करीब 2500 ट्रिलियन घन फीट गैस भंडार मौजूद हैं। इससे भारत की ऊर्जा जरूरतें लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती हैं।

पेट्रोलियम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार केंद्र सरकार इस परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है। सरकार जल्द ही गेल, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दे सकती है। इस योजना की बुनियाद नई दिल्ली स्थित निजी क्षेत्र के समूह साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज की पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट पर रखी गई है। यदि अंतिम मंजूरी मिलती है तो परियोजना को पूरा होने में पांच से सात वर्ष लग सकते हैं।

तकनीकी दृष्टि से भी यह परियोजना बेहद चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है। पाइपलाइन को समुद्र तल से करीब 3450 मीटर की गहराई में बिछाने की योजना है, जिससे यह दुनिया की सबसे गहरी समुद्री पाइपलाइन परियोजनाओं में शामिल हो सकती है। हालांकि हाल के तकनीकी अध्ययनों में गहरे समुद्र में पाइप बिछाने और मरम्मत की आधुनिक तकनीकों के कारण इसे व्यवहारिक बताया गया है। साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज का दावा है कि प्रस्तावित मार्ग पर करीब 3000 मीटर परीक्षण पाइपलाइन पहले ही बिछाई जा चुकी है ताकि समुद्री तल की स्थिति का अध्ययन किया जा सके।

देखा जाये तो मोदी सरकार की ऊर्जा कूटनीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत केवल वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर ही नहीं, बल्कि वैकल्पिक आपूर्ति मार्गों पर भी गंभीरता से काम कर रहा है। भारत अब महंगे और अस्थिर तात्कालिक तरल प्राकृतिक गैस बाजार पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। अधिकारियों का मानना है कि पश्चिम एशिया से सीधी पाइपलाइन भारत को स्थिर और अपेक्षाकृत सस्ती गैस उपलब्ध कराएगी तथा किसी तीसरे देश या समुद्री मार्ग पर निर्भरता भी घटेगी।

इसी बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा भी भारत की ऊर्जा कूटनीति को नई मजबूती देने वाली मानी जा रही है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस यात्रा के दौरान रसोई गैस और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से जुड़े दो महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। भारत के लिए संयुक्त अरब अमीरात कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा तथा तरल प्राकृतिक गैस और रसोई गैस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। प्रधनमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ ऊर्जा सहयोग, द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय हालात पर व्यापक चर्चा करेंगे।

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच यह यात्रा इस बात का संकेत है कि मोदी सरकार केवल वैकल्पिक परियोजनाओं पर ही नहीं, बल्कि खाड़ी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी को भी लगातार मजबूत कर रही है। इसके साथ ही भारत, यूरोप और पश्चिम एशिया को जोड़ने वाले आर्थिक गलियारे तथा उन्नत प्रौद्योगिकी सहयोग पर भी बातचीत होने की संभावना है, जिससे भारत की वैश्विक रणनीतिक स्थिति और सशक्त होगी।

ऐसा काम न करें, जिससे मध्यस्थता प्रक्रिया पर असर पड़े, अदालत का रानी-प्रिया कपूर को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की मां रानी कपूर और उनकी पत्नी प्रिया कपूर को निर्देश दिया कि वे पारिवारिक ट्रस्ट विवाद में चल रही मध्यस्थता कार्यवाही को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाला कोई भी कदम न उठाएं। इससे पहले, 7 मई को, सर्वोच्च न्यायालय ने आरके फैमिली ट्रस्ट से जुड़े मामले में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को मध्यस्थ नियुक्त किया था। सुनवाई के दौरान, अदालत ने कहा कि इस मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाना सभी संबंधित पक्षों के हित में होगा, अन्यथा यह मामला एक लंबी लड़ाई में तब्दील हो सकता है।

न्यायमूर्ति जे बी परदीवाला और उज्ज्वल भुयान की पीठ 80 वर्षीय रानी कपूर द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने 18 मई को निर्धारित रघुवंशी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड की बोर्ड बैठक पर चिंता जताई थी।

उनके वकील ने तर्क दिया कि कंपनी की मूल कंपनी में पर्याप्त हिस्सेदारी है और बैठक के लिए प्रस्तावित कुछ एजेंडा मदों पर चिंता व्यक्त की। इनमें दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और कंपनी के बैंक खातों के संचालन के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं से संबंधित परिवर्तन शामिल थे।

प्रिया कपूर और रघुवंशी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पेश हुए वकीलों ने अदालत को बताया कि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को विवादास्पद नहीं माना जाना चाहिए और यह बैठक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आयोजित की जा रही है। दलीलों का जवाब देते हुए पीठ ने कहा कि हम इस समय और कुछ नहीं कहना चाहते। हमने मध्यस्थ से मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध पहले ही कर दिया है।

फिलहाल, हम विरोधियों से अनुरोध करते हैं कि वे ऐसा कुछ भी न करें जिससे मध्यस्थता की कार्यवाही सीधे तौर पर प्रभावित हो। अदालत ने आगे कहा कि फिलहाल, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं में संशोधन से संबंधित मुद्दों पर 18 मई की बैठक में चर्चा नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि हम मध्यस्थता के संबंध में हुई प्रगति का जायजा लेना चाहेंगे।

UP से मंगाए गए 24 बुलडोजर, बंगाल ने अपनाया योगी मॉडल

शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद पश्चिम बंगाल में सख्त प्रशासनिक अभियान शुरू हो गया है। सिलीगुड़ी में अवैध अतिक्रमणों और अनाधिकृत ढांचों को हटाने के लिए बड़े पैमाने पर विध्वंस अभियान की तैयारी शुरू हो गई है। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्टा ने संकेत दिया है कि जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पुष्टि की है कि अभियान में तेजी लाने के लिए उत्तर प्रदेश से लगभग दो दर्जन बुलडोजर मंगवाए गए हैं। सिलीगुड़ी उपमंडल कार्यालय में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठक हुई, जिसमें उपमंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम), पुलिस आयुक्त, दार्जिलिंग जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) और कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। चर्चा का मुख्य विषय कानून व्यवस्था को मजबूत करना, अवैध निर्माणों को हटाना, मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाना और अवैध शराब की दुकानों, बार और पबों पर कार्रवाई करना था।

बैठक के बाद राजू बिस्टा ने मीडिया को बताया कि सिलीगुड़ी में बड़ी संख्या में अनाधिकृत निर्माण हो चुके हैं और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इन अवैध निर्माणों को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश से दो दर्जन बुलडोजर मंगवाए जा रहे हैं ताकि कार्रवाई तेजी से की जा सके। सांसद ने सिलीगुड़ी नगर निगम के कामकाज की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वह पूरे शहर में अवैध निर्माण को रोकने में पूरी तरह विफल रहा है। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही नगर निगम के अधिकारियों से इस मामले पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए बैठक करेंगे। बिस्टा ने चेतावनी दी कि सरकारी जमीन, नदी किनारे और शहर के अन्य क्षेत्रों पर किए गए अवैध अतिक्रमणों को तुरंत हटाया जाना चाहिए। ऐसा न होने पर प्रशासन बुलडोजर से तोड़फोड़ की कार्रवाई करेगा।

स्वामी एवं प्रकाशक मौ. वसी के लिये मुद्रक नुसरत निशान खान द्वारा कौमी गुलदस्ता प्रिंटर्स, विलेज आमवाला, पोस्ट घंघौरा, देहरादून द्वारा, उत्तराखण्ड-248141 से मुद्रित एवं 5, लेन नम्बर 2, नामदेव एन्क्लेव फेस 2, ब्राहम्णवाला, देहरादून उत्तराखण्ड- 248171 से प्रकाशित। सम्पादक-मौ. वसी,
समस्त विवाद के लिये न्याय क्षेत्र देहरादून मान्य होगा। सम्पर्क- 9411112331
हमारे अखबार के ताजा अंक को ऑनलाइन पढ़ने के लिये www.aawamindia.com वेबसाइट पर जायें।
facebook: www.facebook.com/indiaaawam, youtube:www.youtube.com/@aawamindia,
X:www.x.com/aawamindia, Instagram:https://instagram.com/aawamindia